THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K GADHVI) : (a) to (c) The income-tax Department conducted 7048 searches in various parts of the country during the period from 1st January, 1987 to 31st October, 1987 which resulted in the seizure of *prima facie* unaccounted assets such as cash, jewellery and others amounting to Rs. 94 crores Besides the above, incriminating documents have also been seized during the course of these searches.

(d) and (e) No person has been apprehended during the course of these searches as the Income-tax Act does not provide for the same. No case has so far been launched in the courts for prosecution consequent to the searches conducted during the above period This is so because normally cases for prosecution are launched after the assessments are completed and are decided upon in the first appeal. Also, prosecutions are no launched in cases where the tax-payer, in his statement during search, surrenders the value of unaccounted assets for taxation.

Allocation of Land to displaced persons in West Bengal

1080. SHRI CHITRA BASU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there has been persistent controversy between the Centre and the West Bengal Government over the quantum of land to be allocated to the displaced persons from erstwhile East Pakistan;

(b) if so what are the main issues of such controversy,

(c) whether the dispute has since been resolve; and

(d) if not, what are the reason therefor ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH) : (a) and (b) Under the scheme for regularisation of squatters' colonies, a maximum of 3½ cottahs of land per family is admissible. The Government of West Bengal want the ceiling to be revised to 5 cottahs per family.

(c) No, Sir.

(d) The Government of India consider that the ceiling already prescribed is reasonable and no upward revision is called for.

Sale of One Rupee Currency Note in Black Market

1081 SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the large scale sale of new one rupee currency notes in black market;

(b) if so, what remedial measures Government have taken in the matter; and

(c) whether Government propose to discontinue further printing of such notes in view of high cost of printing of such notes and because of their short durability ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

Bank Robberies in Punjab

1082. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state .

(a) what is the number of bank robberies committed in Punjab since 1st April, 1987;

(b) what is the amount involved in each case and the recovery made. if any; and

(c) what is the number of cases traced and arrests made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI) : (a) to (c) As per available information, the number of dacoities/robberies committed in Public Sector Banks in Punjab since 1st April, 1987, the amount involved in each case, amount recovered, number of persons arrested is given in the attached Statement. [*See* Appendix CXLIV, Annexure No.40.]

The Reserve Bank of India has intimated that none of the cases has been reported to it as having been solved.

वाणिज्य मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति

1083. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, सस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा हिन्दी में यह कार्य किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलो में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए हुए 10 वर्ष हो चुके है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) चालू वर्ष के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की 18-9-1987 को एक बैठक हुई है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कोई भी गैर-सरकारी पर्यवेक्षक आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ख) हिन्दी अनुभाग के अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय में जिन अन्य अनुभागों को 25 फरवरी, 1986 से हिन्दी में सभी कार्य करने के लिए अभिज्ञात किया गया है; रोकड-I, रोकड-II, तथा स्थापना-IV अनुभाग। जहां तक वाणिज्य मंत्रालय के विभागों, सस्थानों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बंध में जानकारी का सम्बन्ध है, उसे संगठनों से एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले दस्तावेजों को मंत्रालय में द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कुछ संगठनों में धारा 3(3) का कार्यान्वयन न होने सम्बंधी कारण, प्रशिक्षित हिन्दी स्टाफ तथा यांत्रिक सुविधाए आदि उपलब्ध न होने जैसी सुविधाओं का अभाव है। उन संगठनों में ग्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दी भाषा का विकास

1084 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी भाषी राज्यों को परियोजनाओं से संबंधित अपने सभी कागजात केवल अंग्रेजी में प्रस्तुत करने पडते है जब कि उन की राजभाषा हिन्दी है और वे वर्ग "क" के अन्तर्गत भी आते है और क्या इसका कारण यह है कि केन्द्र सरकार की केवल एक ही भाषा है, अंग्रेजी जिसमें इन सभी कागजात पर विचार किया जाता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि कोई राज्य अपने इस तरह के कागजात हिन्दी भाषा में भेजता है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद में ही लगभग एक महीना लग जाता है, इस के पश्चात् इन पर विचार किया जाता है, और जब इनका उत्तर भेजा जाता है, तो पुन: इनका हिन्दी में अनुवाद कराने में लगभग एक महीना लग जाता है, जिसके परिणामस्वरूप,